गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 061
दि. 30.06.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

36 साल बाद सरला भट्ट हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, यासीन मलिक समेत पांच पर चार्जशीट, पुराने आतंकी मामलों की भी खुल सकती हैं परतें

श्रीनगर। कश्मीर में आतंकवाद के सबसे दर्दनाक दौर की एक बहुचर्चित घटना, सरला भट्ट अपहरण, दुष्कर्म और हत्या मामले में 36 वर्ष बाद न्यायिक प्रक्रिया ने महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) ने इस मामले में 737 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट विशेष टाडा/पोटा अदालत में दाखिल की है। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को इस कथित आतंकी साजिश का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। एजेंसी का दावा है कि सरला भट्ट की हत्या कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि कश्मीरी पंडित समुदाय में भय फैलाकर उन्हें घाटी से पलायन के लिए मजबूर करने की सुनियोजित आतंकी रणनीति का हिस्सा थी। इस चार्जशीट के साथ अब यासीन मलिक के खिलाफ एक और मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

सरला भट्ट श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआईएमएस) में स्टाफ नर्स थीं। वर्ष 1990 में जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था और बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित परिवार घाटी छोड़ रहे थे, तब भी सरला भट्ट ने अपना घर और नौकरी नहीं छोड़ी। जांच एजेंसी के अनुसार 18 अप्रैल 1990 को अस्पताल के निकट से उनका अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि उन्हें अमानवीय यातनाएं देने के बाद श्रीनगर के उमर कॉलोनी, मालबाग क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने उस समय पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय में गहरा भय पैदा कर दिया था।

एसआईए द्वारा दायर चार्जशीट में यासीन मलिक के अलावा खुर्शीद अहमद चालकू, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सूफी उर्फ इदरीस तथा गुलाम मोहम्मद टपलू को भी आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार खुर्शीद अहमद चालकू ने कथित तौर पर सरला

भट्ट पर गोली चलाई थी। एजेंसी का कहना है कि चालकू के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) भाग जाने की आशंका है और उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अन्य तीन आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है।

जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि सरला भट्ट पर "मुखबिर" होने का आरोप पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत था। एसआईए के अनुसार 8 अप्रैल 1990 को नरवारा क्षेत्र में जेकेएलएफ आतंकियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद यासीन मलिक और उसके सहयोगियों को संदेह हुआ कि किसी कश्मीरी पंडित नर्स ने पुलिस को सूचना दी थी। इसी संदेह के आधार पर सरला भट्ट को निशाना बनाया गया। हालांकि जांच में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को कोई सूचना दी थी। एजेंसी का दावा है कि उन्हें केवल कश्मीरी पंडित समुदाय में दहशत फैलाने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया।

मार्च 2024 में जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर यह मामला एसआईए को सौंपा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने दशकों पुराने रिकॉर्ड, पुलिस दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट, बैलिस्टिक परीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजों का व्यापक अध्ययन किया। कई बुजुर्ग गवाहों से दोबारा पूछताछ की गई और घटनाक्रम को नए सिरे से जोड़कर पूरे मामले की पुनर्निर्मित जांच की गई। एजेंसी का कहना है कि इतने लंबे समय के बाद भी उपलब्ध साक्ष्यों ने आरोपों को मजबूत आधार प्रदान किया है।

चार्जशीट में वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। जांच के दौरान घटनास्थल से बरामद तीन कारतूसों की बैलिस्टिक जांच कराई गई, जिसमें पुष्टि हुई कि तीनों गोलियां एक ही 7.62×39 मिमी हथियार से चलाई गई थीं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के रूप में फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के एक प्रमाणित टेलीविजन साक्षात्कार सहित अन्य सामग्री को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। एसआईए का दावा है कि उपलब्ध वैज्ञानिक, परिस्थितिजन्य और दस्तावेजी साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि सरला भट्ट की हत्या जेकेएलएफ की एक सुनियोजित आतंकी साजिश का हिस्सा थी।

जांच एजेंसी का यह भी कहना है कि सरला भट्ट हत्याकांड की दोबारा जांच के दौरान कई अन्य पुराने और अब तक अनसुलझे आतंकी मामलों से जुड़े नए सुराग और संभावित गवाह भी सामने आए हैं। इनमें जस्टिस नीलकंठ गंजू, टिक्का लाल टपलू तथा कवि सरवानंद कौल प्रेमी की हत्याओं से जुड़े मामले भी शामिल हैं। एसआईए इन मामलों की भी जांच आगे बढ़ा रही है और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद संबंधित अदालतों में अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। यदि ऐसा होता है तो कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर की कई लंबे समय से लंबित घटनाओं में भी न्यायिक प्रक्रिया को नई गति मिल सकती है।

सोशल मीडिया बना वन्यजीव तस्करी का नया अड्डा, फेसबुक पर बिक रहे बंदर, पैंगोलिन और गैंडे के सींग; वैश्विक रिपोर्ट से सनसनी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब केवल संवाद और मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों की अवैध तस्करी के बड़े बाजार के रूप में भी उभर रहे हैं। स्विट्जरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्लोबल इनीशिएटिव अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (जीआई-टीओसी) की ताजा रिपोर्ट ने इस गंभीर खतरे का खुलासा करते हुए बताया है कि दुनिया की प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी मेटा के प्लेटफॉर्म, विशेषकर फेसबुक पर बंदरों, गैंडे के सींग (राइनो हॉर्न), मृत पैंगोलिन, मॉनिटर लीजर्ड (विशाल छिपकली) तथा अन्य दुर्लभ और संरक्षित वन्यजीवों एवं उनसे बने उत्पादों की खुलेआम खरीद-फरोख्त की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार शिकायतों के बावजूद कई विज्ञापन लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बने रहे, जिससे सोशल मीडिया कंपनियों की निगरानी व्यवस्था और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जीआई-टीओसी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 से मार्च 2026 के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वन्यजीवों और उनसे तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए लगभग 20 हजार विज्ञापन प्रकाशित किए गए। इन विज्ञापनों के माध्यम से करीब 2.60 लाख वन्यजीव उत्पादों की बिक्री का प्रयास किया गया। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इन विज्ञापनों में लगभग एक-तिहाई केवल फेसबुक पर पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मामलों में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद संबंधित पोस्ट हटाए नहीं गए, जिससे अवैध वन्यजीव व्यापार को बढ़ावा मिलता रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि तस्कर सोशल मीडिया का बेहद सुनियोजित तरीके से उपयोग कर रहे हैं। वे दुर्लभ जानवरों, उनके अंगों और उनसे बने उत्पादों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से कीमत का उल्लेख नहीं करते। इच्छुक खरीदारों को पोस्ट पर टिप्पणी करने के बजाय निजी संदेश भेजने के लिए कहा जाता है। इसके बाद पूरी खरीद-बिक्री की बातचीत निजी चैट के माध्यम से होती है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इस अवैध नेटवर्क तक पहुंचना और भी कठिन हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तरीका डिजिटल प्लेटफॉर्म को संगठित वन्यजीव तस्करी का नया माध्यम बना रहा है। रिपोर्ट में विशेष रूप से थाईलैंड का उल्लेख किया गया है, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से मृत पैंगोलिन, मॉनिटर लीजर्ड और अन्य संरक्षित वन्यजीवों की बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त की जा रही है। थाईलैंड के वाइल्डलाइफ फ्रेंड्स फाउंडेशन के मुख्य परिचालन अधिकारी टॉम टेलर ने कहा कि उनकी संस्था ने ऐसे अनेक विज्ञापनों की शिकायत संबंधित प्लेटफॉर्म से की, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए वन्यजीवों की तस्करी करने वाले लोगों के साथ-साथ ऐसे विज्ञापनों को स्थान देने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इससे विलुप्तप्राय प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसे मेटा के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी वन्यजीवों और उनके उत्पादों से जुड़े विज्ञापन बड़ी संख्या में पाए गए। टिकटॉक और स्नैपचैट पर भी ऐसे विज्ञापन सामने आए, हालांकि इन प्लेटफॉर्म पर सीमित समय तक पोस्ट दिखाने की सुविधा होने के कारण कई विज्ञापन स्वतः हट जाते हैं। इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि विज्ञापन हटने से पहले ही खरीदार और विक्रेता आपस में संपर्क स्थापित कर लेते हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद भी मेटा की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। दिलचस्प बात यह है कि इसी महीने मेटा सहित 11 प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर वन्यजीवों और उनसे बने उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए संयुक्त प्रयास करने की घोषणा की है। मेटा वर्ष 2018 से कोएलिशन टू एंड वाइल्डलाइफ ट्रैफिकिंग ऑनलाइन का सदस्य भी है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से होने वाली वन्यजीव तस्करी पर रोक लगाना है। इसके बावजूद ताजा रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रतिबंधों और नीतियों के बावजूद अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है।

रिपोर्ट में जिन वन्यजीवों का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, उनमें पैंगोलिन प्रमुख है। इसे दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी माना जाता है। इसके शल्कों का उपयोग कुछ पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में किया जाता है, जबकि इसका मांस भी कई देशों में अवैध रूप से बेचा जाता है। अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संगठनों के अनुसार इन दावों का पर्याप्त वैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध नहीं है, फिर भी अवैध मांग के कारण इसकी आबादी तेजी से घट रही है। इसी तरह मॉनिटर लीजर्ड की त्वचा से महंगे बेल्ट, बैग और अन्य चमड़े के उत्पाद बनाए जाते हैं, जबकि गैंडे के सींग की अवैध तस्करी मुख्य रूप से पारंपरिक चिकित्सा और विलासिता की वस्तुओं के बाजार से जुड़ी हुई है। इन तीनों प्रजातियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण की आवश्यकता वाली प्रजातियों में गिना जाता है।

वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म की निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पहचान प्रणाली और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई को और अधिक प्रभावी नहीं बनातीं, तो डिजिटल माध्यम वन्यजीव तस्करी के सबसे बड़े नेटवर्क में बदल सकता है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कर्नाटक में सियासी टकराव, एसआईआर से पहले कांग्रेस और चुनाव आयोग आमने-सामने

बेंगलुरु। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन–एसआईआर) अभियान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मंगलवार से प्रस्तावित इस अभियान के शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस द्वारा उठाई गई आपत्तियों और सवालों का संतोषजनक जवाब दिए बिना चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। वहीं, चुनाव आयोग ने अभियान को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है।

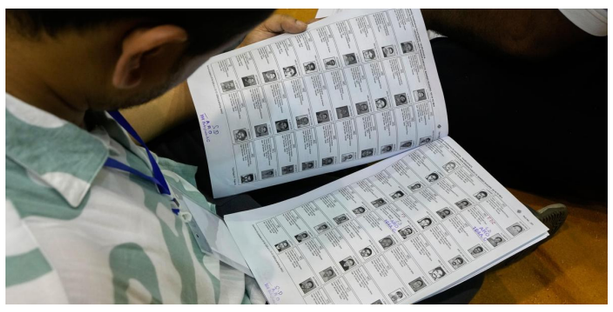

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने सोमवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे पूरी पारदर्शिता और सभी पक्षों के विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब चुनाव आयोग को पहले देना चाहिए। उनका कहना था कि जब तक इन आशंकाओं और आपत्तियों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

प्रियांक खरगे ने यह भी बताया कि राज्य सरकार इस पूरे विषय पर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और आगे की रणनीति तय करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी राजनीतिक दलों के विश्वास के अनुरूप हो, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 29 जून से 29 जुलाई तक राज्यभर में घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान निर्वाचन अधिकारियों की टीमें मतदाताओं के विवरण का भौतिक सत्यापन करेंगी, नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करेंगी तथा मृत, स्थानांतरित या अपात्र मतदाताओं के नामों की समीक्षा भी की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबु कुमार भी इस अभियान को लेकर बेंगलुरु में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे। आयोग की ओर से उम्मीद जताई गई है कि मतदाता सत्यापन अभियान में नागरिक सक्रिय सहयोग करेंगे, जिससे आगामी चुनावों के लिए विश्वसनीय और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जा सके।

इस बीच कांग्रेस ने भी पूरे राज्य में जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर पैनी नजर रखें और यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया जाता है या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसकी तत्काल जानकारी पार्टी और संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को दें। कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना आवश्यक है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर शुरू हुआ यह विवाद आने वाले दिनों में और राजनीतिक रूप ले सकता है। एक ओर चुनाव आयोग इसे नियमित और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहा है, वहीं कांग्रेस इस अभियान को लेकर अपनी शंकाओं के समाधान की मांग पर अड़ी हुई है। अब सभी की निगाह इस बात पर है कि चुनाव आयोग कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर क्या रुख अपनाता है और मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान किस प्रकार आगे बढ़ता है।

राम मंदिर चंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा- 'अभी आसमान नहीं गिर पड़ेगा'

नई दिल्ली। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए करोड़ों रुपये के चंदे में कथित अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं दिखती और इसे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के नियमित रूप से कार्य शुरू होने पर सूचीबद्ध किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई अवकाश समाप्त होने के बाद पहले सप्ताह में की जाएगी।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। याचिका में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के कथित गबन, दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अथवा विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का अनुरोध किया गया है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुंदरेश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की ऐसी क्या आवश्यकता है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और राज्य सरकार जिस तरीके से मामले को देख रही है, उससे निष्पक्ष जांच को लेकर संदेह पैदा होता है। उनका कहना था कि यदि समय रहते अदालत हस्तक्षेप नहीं करती तो महत्वपूर्ण साक्ष्यों के प्रभावित होने की आशंका है। इस पर पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "आसमान नहीं गिर पड़ेगा।" अदालत ने कहा कि मामला अदालत के दोबारा पूर्ण रूप से खुलने के बाद पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के पास जटिल वित्तीय लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के लिए आवश्यक विशेषज्ञता तथा फोरेंसिक संसाधनों का अभाव है। याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज किए ही जांच शुरू कर दी गई, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। याचिका में यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि यदि स्वतंत्र एजेंसी से शीघ्र जांच नहीं कराई गई तो सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

याचिका दो अधिवक्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए जाएं तथा मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र विशेष जांच दल से कराई जाए। उनका कहना है कि इससे न केवल संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सकेगा, बल्कि धन के प्रवाह का पता लगाने, कथित जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और जांच के दौरान किसी भी प्रकार के साक्ष्य से छेड़छाड़ को रोका जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और केवल तत्काल सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार किया है। अदालत ने संकेत दिया कि नियमित पीठ के समक्ष निर्धारित समय पर मामले की सुनवाई होगी, जहां याचिका में लगाए गए आरोपों और जांच संबंधी मांगों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। फिलहाल, मामले में आरोपों की सत्यता पर न्यायालय ने कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है और उनका परीक्षण आगे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

संपादकीय

आस्था से छल

अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए दान और कीमती सामान की हेराफेरी की घटनाओं ने देश-विदेश के रामभक्तों को विचलित किया है। कभी आमजन में कहा जाता था कि 'भगवान से डर', लेकिन पैसे की हवस देखिए कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े चंद लोगों ने भगवान के घर में चोरी करने में कोई डर महसूस नहीं किया। ये प्रबंधन व व्यवस्था की पारदर्शिता की खोट तो है ही, मानवीय मूल्यों के पतन की पराकाष्ठा भी है कि मंदिर में चढ़ावे की देखरेख को तैनात लोग ही चोरी-चकारी में लिप्त हो जाएं। इस मामले में विपक्ष के तीखे हमले और जनाक्रोश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए आनन-फानन में एसआईटी गठित की, रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, प्राथमिकी दर्ज की और वीरवार को प्रबंधन से जुड़े आठ कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन अपने आराध्य राम के चढ़ावे की चोरी से आहत भक्तों के जख्मों पर शायद तभी मरहम लगेगी, जब दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। निश्चित ही यह चोरी का प्रकरण भाजपा व संघ को परेशान करने वाला है। उस राजनीतिक दल के लिये, जिसके कभी दो सांसद हुआ करते थे और राम मंदिर की मुहिम से हासिल जनसमर्थन से केंद्र व तमाम राज्यों में उसकी सरकारें बनी हैं। खासकर, भाजपा के लिए यह मुद्दा परेशानी का सबब हो सकता है क्योंकि राम जन्म भूमि वाले प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस मुद्दे को लेकर भाजपा राज्य की सत्ता में आती रही है, उस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर होगा। निस्संदेह, इस प्रकरण से राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट तो पहुंची है। सवाल राम मंदिर ट्रस्ट की नाकामी पर भी उठेंगे कि उसने समय रहते इस चोरी को क्यों नहीं पकड़ा। बेहतर होता कि दोषियों के खिलाफ ट्रस्ट की तरफ से स्वतः प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाती। सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों ट्रस्ट चंदे की रकम का हिसाब-किताब विश्वसनीय तरीके से नहीं रख पाया। निश्चय ही इस प्रकरण से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की साख भी दांव पर लगी है। वह उन भक्तों की भावनाओं की रक्षा नहीं कर पाया, जिन्होंने मंदिर निर्माण से लेकर अब तक दिल खोलकर दान दिया। जब चंदा प्रबंधन से जुड़े लोगों के घर से लाखों की नकदी बरामद हुई और चोरी के पैसे से जमीन खरीदने के आरोप सामने आए तो भक्तों की आस्था पर आंच आना स्वाभाविक ही है। आरोप सिर्फ नकदी के हेरफेर के ही नहीं लगे बल्कि कीमती गहनों को खुर्दबुर्द करने के भी लगे। वहीं प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान दान में मिली चांदी की छड़ों के गायब होने का भी आरोप है। बहरहाल, 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले सामने आए इस विवाद ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष जहां दोषियों पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है, वहीं भाजपा इन आरोपों को अयोध्या को बदनाम करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश बता रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि जिन भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए पांच सौ साल तक इंतजार किया, उन्हें एसआईटी जांच अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। उनकी दलील है कि इस शर्मनाक मामले की तह तक जाने के लिये एक पारदर्शी और समय-सीमा के भीतर होने वाली जांच बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल चंदे के रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने और स्वतंत्र ऑडिट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों के दान और धार्मिक आस्था से जुड़े मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह प्रकरण देश के बड़े धार्मिक संस्थानों में चंदे के प्रबंधन में पारदर्शिता व सतर्कता की मांग करता है। चंदे का नियमित ऑडिट किया जाना, तकनीक आधारित प्रबंधन, डिजिटल ट्रैकिंग और स्वतंत्र निगरानी वाले आधुनिक सिस्टम की जरूरत को दर्शाता है। निस्संदेह, राम मंदिर भारत व विदेशों में बसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आकांक्षा का प्रतीक है। श्रद्धालुओं का भरोसा बनाये रखने के लिये हर आक्षेप की पारदर्शिता से जांच जरूरी है।

चीन देखता रह गया, हिंद महासागर में भारत ने बना ली मजबूत घेराबंदी

> "मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच नौ महत्वपूर्ण समझौते हुए। इनमें प्रत्यर्पण संधि सबसे अधिक सामरिक महत्व रखती है। हिंद महासागर क्षेत्र लंबे समय से समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अंतरराष्ट्रीय अपराधों की चुनौती से जूझता रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में केवल एक सहभागी शक्ति नहीं, बल्कि स्थिरता, सुरक्षा और विकास का सबसे भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। सेशेल्स की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई यह यात्रा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही।प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की संसद को संबोधित करते हुए जिस प्रकार हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाने की बात कही, वह भारत की दूरदर्शी समुद्री नीति का स्पष्ट संकेत है। भारत ने यह संदेश दिया कि हिंद महासागर केवल समुद्री व्यापार का मार्ग नहीं, बल्कि सामरिक संतुलन, आर्थिक समृद्धि और वैश्विक शक्ति संरचना का केंद्र बनने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में मोदी सरकार की विदेश नीति का आत्मविश्वास और परिपक्वता साफ दिखाई दी। सेशेल्स को भारत ने जिस सम्मान और साझेदारी का भरोसा दिया, उसने यह साबित किया कि नई दिल्ली छोटे देशों को भी बराबरी और सम्मान के साथ साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है।

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच नौ महत्वपूर्ण समझौते हुए। इनमें प्रत्यर्पण संधि सबसे अधिक सामरिक महत्व रखती है। हिंद महासागर क्षेत्र लंबे समय से समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अंतरराष्ट्रीय अपराधों की चुनौती से जूझता रहा है। ऐसे में प्रत्यर्पण समझौता और समुद्री सुरक्षा सहयोग भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत करने वाला कदम है। इससे भारत को पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और निगरानी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत और सेशेल्स की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि भारत ने सेशेल्स को तेज गश्ती पोत, नौकाएं, एंबुलेंस और अन्य उपयोगी वाहन भेंट किए। भारतीय नौसेना के युद्धपोत और सर्वेक्षण पोत का सेशेल्स पहुंचना हिंद महासागर में भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रदर्शन भी था।

साथ ही भारत ने सेशेल्स के लिए एक सौ पचहत्तर मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर यह भी दिखाया कि उसकी विदेश नीति केवल रणनीतिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास आधारित साझेदारी पर आधारित है। सामाजिक आवास, शिक्षा, परिवहन, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारत का सहयोग यह दर्शाता है कि नई दिल्ली अपने साझेदार देशों के विकास को अपनी प्राथमिकता मानती है। मोदी सरकार की यही नीति भारत को अन्य वैश्विक शक्तियों से अलग पहचान देती है।

इस यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल और आर्थिक सहयोग भी रहा। भारत और सेशेल्स के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार, प्रत्यक्ष नौवहन संपर्क और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर हुए समझौते भविष्य की आर्थिक संरचना को बदलने वाले कदम हैं। भारत की डिजिटल सार्वजनिक संरचना को सेशेल्स में लागू करने की पहल यह साबित करती है कि भारत अब तकनीकी समाधान देने वाली वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है। यह मोदी सरकार की उस नीति का परिणाम है जिसमें तकनीक को जनकल्याण और वैश्विक साझेदारी का आधार बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन और छोटे द्वीपीय देशों की चुनौतियों को जिस मजबूती से उठाया, वह भी भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा कि जिन देशों ने जलवायु संकट पैदा नहीं किया, उन्हें उसका सबसे बड़ा बोझ नहीं उठाना चाहिए। यह बयान विकसित देशों की दोहरी नीतियों पर सीधा प्रहार भी था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी आधारभूत ढांचा गठबंधन और हरित ऊर्जा अभियानों के माध्यम से पहले ही विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बना ली है। सेशेल्स द्वारा भारत की पहल में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देशों के बीच भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है।

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स द्वारा दिया गया "ब्लू होराइजन के संरक्षक" सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह सम्मान पहली बार किसी नेता को दिया गया और इससे यह संदेश गया कि हिंद महासागर क्षेत्र भारत को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखता है। पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और समुद्री संसाधनों के संतुलित उपयोग को लेकर भारत की प्रतिबद्धता ने छोटे द्वीपीय देशों में विश्वास पैदा किया है।

सामरिक दृष्टि से देखें तो यह यात्रा चीन की बढ़ती समुद्री सक्रियता के बीच भारत की मजबूत जवाबी रणनीति का हिस्सा भी है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार बंदरगाह, आधारभूत ढांचे और कर्ज आधारित परियोजनाओं के जरिए प्रभाव बढ़ाने में लगा है। इसके मुकाबले भारत ने सहयोग, विश्वास और साझा विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि सेशेल्स जैसे देश भारत को केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि दीर्घकालिक साझेदार मानते हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति ने पिछले एक दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को अभूतपूर्व मजबूती दी है।

साथ ही सेशेल्स की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर भारतीय सेना और नौसेना की ऐतिहासिक भागीदारी ने इसे भारत की सामरिक शक्ति और क्षेत्रीय प्रभाव के प्रदर्शन में बदल दिया। असम रेजिमेंट के जवानों, भारतीय नौसेना के बैंड और युद्धपोतों की मौजूदगी ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सुरक्षा का सबसे विश्वसनीय स्तंभ है। राजधानी विक्टोरिया में जब भारतीय सैनिकों ने कदमताल की और असम रेजिमेंट का प्रसिद्ध युद्धगान गूंजा, तब वह केवल सैन्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारत और सेशेल्स के बीच दशकों पुराने भरोसे और रक्षा सहयोग का जीवंत प्रतीक था। युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षाक की उपस्थिति ने हिंद महासागर में भारत की समुद्री क्षमता और रणनीतिक पहुंच को और अधिक प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। यह संदेश भी साफ था कि मोदी सरकार हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सैन्य और सामरिक उपस्थिति को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बहरहाल, कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा स्पष्ट संकेत देती है कि आने वाले समय में हिंद महासागर की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका निर्णायक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स यात्रा ने यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार की विदेश नीति दूरदर्शी, संतुलित और रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती उपस्थिति केवल सामरिक शक्ति का विस्तार नहीं, बल्कि विश्वास, विकास और साझी समृद्धि की नई कहानी है।

प्रेरणा

जीवन की सबसे बड़ी विजय है मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना

संसार में मनुष्य अनेक प्रकार की विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। कोई धन कमाने को सफलता मानता है, कोई सत्ता प्राप्त करने को जीवन का उद्देश्य समझता है, तो कोई अपने शत्रुओं को परास्त करके स्वयं को विजेता घोषित कर देता है। लेकिन इन सभी विजयों से कहीं बड़ी एक ऐसी विजय है, जिसे बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। वह है मृत्यु के शाश्वत सत्य को स्वीकार करने की विजय। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु अनिवार्य है, उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह न सफलता में अहंकार करता है और न असफलता में टूटता है। उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है, जो उसे परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीवन को देखने की शक्ति देती है। फारस के न्यायप्रिय सम्राट नौशेरवां का एक प्रसंग इसी गहन सत्य का परिचय कराता है।

एक समय राज्य की सीमाओं पर भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हो रहा था। वीर सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्धभूमि में डटे हुए थे। सम्राट नौशेरवां युद्ध शिविर में अपने सेनापतियों और मंत्रियों के साथ आगे की योजना पर विचार कर रहे थे। तभी एक गुप्तचर तेजी से उनके सामने पहुंचा। उसके चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने उत्साह से कहा, "महाराज, आपके लिए अत्यंत शुभ समाचार है। आपका सबसे बड़ा शत्रु युद्ध करते हुए मारा गया है। अब हमारी जीत निश्चित है।"

यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों को लगा कि सम्राट अवश्य प्रसन्न होंगे, लेकिन नौशेरवां ने शांत भाव से उत्तर दिया, "यदि तुम यह कहते कि आज मृत्यु ने संसार से विदा ले ली है और अब कोई मनुष्य कभी नहीं मरेगा, तब मैं इसे वास्तव में शुभ समाचार मानता। किसी व्यक्ति का मर जाना कोई विशेष समाचार नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है। आज वह चला गया, कल मैं भी चला जाऊंगा और एक दिन तुम भी इस संसार को छोड़ दोगे। इसलिए किसी की मृत्यु पर अत्यधिक प्रसन्न होना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अज्ञानता है।" सम्राट के इन शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को गहरे चिंतन में डाल दिया। वास्तव में मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वह स्वयं भी उसी यात्रा का यात्री है, जिसका अंत मृत्यु पर होता है। वह दूसरों की मृत्यु को तो सामान्य घटना मान लेता है, लेकिन स्वयं को इस नियम से अलग समझने लगता है। यही भ्रम उसके भीतर अहंकार पैदा करता है। जब तक मनुष्य को लगता है कि उसके पास असीम समय है, तब तक वह जीवन के वास्तविक मूल्य को नहीं समझ पाता।

मृत्यु का स्मरण जीवन को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे अधिक मूल्यवान बना देता है। जिस प्रकार सीमित जल वाला पात्र अधिक सावधानी से उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार सीमित जीवन भी हमें प्रत्येक क्षण का महत्व समझाता है। यदि मनुष्य को यह विश्वास हो जाए कि वह कभी नहीं मरेगा, तो शायद वह समय, संबंधों और नैतिक मूल्यों की कोई परवाह ही न करे। लेकिन मृत्यु की निश्चितता उसे यह सिखाती है कि प्रत्येक दिन एक अवसर है, जिसे सार्थक बनाना चाहिए।

भारतीय दर्शन में भी मृत्यु को भय का विषय नहीं, बल्कि परिवर्तन का द्वार माना गया है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने जीवन को एक यात्रा कहा है, न कि स्थायी निवास। यह शरीर एक पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन में संग्रह से अधिक सदाचार पर ध्यान देता है। उसे पता होता है कि धन, भवन, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएंगे। उसके साथ केवल उसके कर्म चलेंगे।

आज का मनुष्य अपने भविष्य की योजनाएं बनाने में इतना व्यस्त है कि वर्तमान को जीना ही भूल जाता है। वह वर्षों तक धन इकट्ठा करने में लगा रहता है, लेकिन अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ पल बिताने का समय नहीं निकाल पाता। वह सफलता के पीछे भागते-भागते अपने स्वास्थ्य, संबंधों और मानसिक शांति को खो देता है। फिर एक दिन अचानक कोई घटना उसे याद दिलाती है कि जीवन उतना लंबा नहीं है, जितना उसने समझ रखा था। तभी उसे एहसास होता है कि वास्तव में सबसे मूल्यवान वस्तु समय था, जिसे वह बिना सोचे-समझे गंवाता रहा।

सम्राट नौशेरवां ने अपने व्यवहार से यह भी बताया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता। वास्तविक नेतृत्व वह है, जिसमें विजय के समय भी विनम्रता बनी रहे। किसी शत्रु की मृत्यु पर उत्सव मनाना आसान है, लेकिन यह समझना कठिन है कि वह भी उसी प्रकृति का एक अंश था, जिसका हिस्सा हम स्वयं हैं। यही विचार मनुष्य को संवेदनशील बनाता है और उसके भीतर करुणा का विकास करता है।

जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम स्वयं को स्थायी मान बैठते हैं। हम घर बनाते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं, नाम कमाते हैं और सोचते हैं कि यही हमारी पहचान है। लेकिन इतिहास गवाह है कि समय ने बड़े-बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया। जिन राजाओं के नाम से संसार कांपता था, आज उनके महल केवल खंडहर बनकर रह गए हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि संसार में स्थायी केवल परिवर्तन है।

यदि मनुष्य प्रतिदिन कुछ क्षण यह विचार करे कि एक दिन उसे भी इस संसार से विदा होना है, तो उसका जीवन स्वतः बदल जाएगा। वह दूसरों को क्षमा करना सीख जाएगा। वह छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होगा। वह ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहेगा। वह अपने परिवार और समाज के प्रति अधिक उत्तरदायी बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वह अपने हर कर्म को इस प्रकार करेगा कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे सम्मान के साथ याद करें।

वास्तव में अमरता शरीर की नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों की होती है। जिन लोगों ने मानवता के लिए कार्य किया, सत्य और न्याय का मार्ग अपनाया तथा दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया, वे आज भी लोगों के हृदयों में जीवित हैं। उनके शरीर समाप्त हो गए, लेकिन उनके आदर्श आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही वास्तविक अमरत्व है, जिसे प्रत्येक मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

सम्राट नौशेरवां का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि मृत्यु को शत्रु नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक नियम मानना चाहिए। जिस दिन हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होने लगता है। तब हम दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।

Europe Heatwave से जनता बेहाल, सड़कें और पटरियाँ पिघल रहीं, Fan और AC लूट रहे लोग, France में टूटा मौतों का रिकॉर्ड

यूरोप इस समय भीषण गर्मी की ऐसी मार झेल रहा है, जिसने जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन व्यवस्था और ऊर्जा तंत्र को गंभीर संकट में डाल दिया है। पिछले कुछ दिनों में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, चेक गणराज्य, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और इटली सहित कई देशों में तापमान ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि 21 जून के बाद से यूरोप में अत्यधिक तापमान के कारण 1300 से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें अकेले फ्रांस में लगभग 1000 अतिरिक्त मौतें सामने आई हैं और इनमें 85 प्रतिशत मृतकों की आयु 65 वर्ष से अधिक थीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापवृद्धि के कारण कभी पीढ़ी में एक बार आने वाली भीषण गर्मी अब लगभग हर वर्ष देखने को मिल रही है। उन्होंने इसे "मूक हत्यारा" बताया, क्योंकि यूरोप के अधिकांश घर, दफ्तर और विद्यालय इतनी गर्मी के लिए तैयार नहीं हैं। संगठन ने यूरोपीय देशों से हीट हेल्थ एक्शन योजना लागू करने और स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है।

हम आपको बता दें कि फ्रांस इस संकट का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार 24 जून के बाद से वहां सामान्य से करीब 1000 अधिक मौतें दर्ज हुई हैं। सबसे अधिक असर उन इलाकों में देखा गया जहां रेड अलर्ट जारी किया गया था। पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में घरों के भीतर हुई मौतों में तेज वृद्धि देखी गई है। एजेंसी ने कहा कि यह स्थिति समाज में अकेले रह रहे बुजुर्गों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी और सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

हम आपको बता दें कि फ्रांस में हालात इतने गंभीर हो गए कि अस्पतालों में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। पेरिस के सरकारी अस्पतालों में लगातार दूसरे दिन लगभग 3000 लोग गर्मी से जुड़ी समस्याओं के उपचार के लिए पहुंचे, जो सामान्य से लगभग एक तिहाई अधिक है। राजधानी के सभी 38 अस्पतालों में आपात योजना लागू करनी पड़ी। साथ ही चिकित्सकीय सहायता केंद्रों पर आने वाली कॉल में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

गर्मी ने केवल स्वास्थ्य सेवाओं को ही नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। जर्मनी में तेज गर्मी के कारण सड़कों की कंक्रीट की परतें फट गईं और कई राजमार्ग बंद करने पड़े। रेल सेवाएं बाधित हुईं और देश की रेल कंपनी ने गैरजरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। फ्रांस में सड़कें पिघलने, बिजली आपूर्ति प्रभावित होने और रेल सेवाओं में देरी की घटनाएं सामने आईं। स्विट्जरलैंड में नदी के पानी का तापमान बढ़ने से बेजनाउ परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर अस्थायी रूप से बंद करने पड़े।

यूरोप के कई देशों में तापमान ने ऐतिहासिक रिकार्ड बनाए। जर्मनी में तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि चेक गणराज्य में 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ब्रिटेन में जून का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ, जहां तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। डेनमार्क में 1874 के बाद का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। स्विट्जरलैंड के बासेल में 38.8 डिग्री सेल्सियस और स्पेन में 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। फ्रांस में औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो वहां के मौसम इतिहास में पहली बार हुआ।

विशेषज्ञों का कहना है कि मानवजनित जलवायु परिवर्तन के बिना इतनी तीव्र और लगातार गर्मी लगभग असंभव थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन चुका है और आने वाले वर्षों में ऐसी हीटवेव और अधिक सामान्य हो सकती हैं।

साथ ही फ्रांस में 18 जून के बाद से कम से कम 74 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। अधिकतर हादसे बिना निगरानी वाले तालाबों, नदियों और झीलों में हुए, जहां लोग गर्मी से राहत पाने पहुंचे थे। ब्रिटेन में भी गर्मी के दौरान नदी और झीलों में डूबने से कई लोगों की जान गई। प्रशासन ने लोगों से असुरक्षित जलाशयों में जाने से बचने की अपील की है।

इटली में रोम, मिलान, फ्लोरेंस और वेनिस सहित 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी है। पर्यटक फव्वारों और छायादार स्थानों में राहत खोजते दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की गई, क्योंकि तेज धूप में शराब सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। देखा जाये तो गर्मी ने यूरोप के आवासीय ढांचे की कमजोरियां भी उजागर कर दी हैं। अधिकांश यूरोपीय घर ठंडे मौसम को ध्यान में रखकर बनाए गए थे और वहां वातानुकूलन व्यवस्था व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार यूरोप के केवल लगभग 20 प्रतिशत घरों में वातानुकूलन की सुविधा है। पुराने भवनों और ऐतिहासिक इमारतों में नए वातानुकूलन यंत्र यानि एसी लगाना कठिन और महंगा है।

इसी कारण पोर्टेबल वातानुकूलन यंत्रों की मांग अचानक बढ़ गई है। एशियाई कंपनियों को इसका बड़ा लाभ मिला है। सैमसंग, एलजी, मित्सुबिशी, मिडिया और ग्री जैसी कंपनियों ने यूरोप में बिक्री में तेज वृद्धि दर्ज की है। चीन से पश्चिमी यूरोप को पोर्टेबल वातानुकूलन यंत्रों का निर्यात 2026 के पहले पांच महीनों में 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया।

फ्रांस में तो वातानुकूलन यंत्रों एसी और पंखों की खरीद को लेकर कई स्थानों पर अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई। पेरिस के निकट ला डेफांस में एक दुकान खुलते ही सैकड़ों लोग सस्ते वातानुकूलन यंत्र खरीदने के लिए अंदर घुस पड़े।

अभियान

जहाँ स्वयं श्रीहरि शिला बनकर देते हैं भक्तों को दिव्य दर्शन

हिमालय की दिव्य गोद में स्थित श्री बदरीविशाल धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भगवान श्रीहरि का वह दिव्य लोक माना जाता है जहाँ पृथ्वी और वैकुण्ठ का अद्भुत संगम होता है। यहाँ की प्रत्येक शिला, प्रत्येक जलधारा, प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक कण में भगवान नारायण की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। जब कोई श्रद्धालु बदरीनाथ धाम की पवित्र भूमि पर कदम रखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह सांसारिक जीवन की सीमाओं को पार कर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर चुका हो। स्कन्द पुराण, विष्णु पुराण और अनेक वैष्णव ग्रंथों में बदरिकाश्रम को भगवान विष्णु की तपोभूमि और मोक्षभूमि कहा गया है। इसी पवित्र धाम में पाँच ऐसी दिव्य शिलाएँ विद्यमान हैं जिनमें स्वयं भगवान श्रीहरि का नित्य निवास माना गया है। इन पंचशिलाओं के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, मन निर्मल होता है और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा का संचार होता है।

पुराणों में वर्णित है कि एक समय भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा कि जो मनुष्य संसार के बड़े से बड़े पापों से ग्रसित हो, यदि वह श्रद्धापूर्वक बदरीपुरी पहुँचकर अग्नि तीर्थ में स्नान करे और भगवान की इन पाँच दिव्य शिलाओं—नारद शिला, नृसिंह शिला, वाराही शिला, गरुड़ शिला और मार्कण्डेय शिला—का दर्शन करे, तो उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप भी क्षीण होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि इन शिलाओं में केवल पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य चेतना विराजमान है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से संत, ऋषि, योगी और भक्त इन शिलाओं को साक्षात श्रीहरि का स्वरूप मानकर प्रणाम करते आए हैं।

बदरीनाथ धाम की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब भक्त भगवान बदरीविशाल के दर्शन के साथ इन पंचशिलाओं का भी श्रद्धापूर्वक दर्शन करे। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान की उन लीलाओं का स्मरण है जिनमें उन्होंने अपने परम भक्तों को दर्शन देकर उन्हें अमर बना दिया। इन शिलाओं के माध्यम से भगवान आज भी अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, वह कभी उनसे दूर नहीं होता।

देवर्षि नारद का नाम भगवान विष्णु के परम भक्तों में सबसे पहले लिया जाता है। वे सदा "नारायण-नारायण" का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में भगवान का संदेश पहुँचाते हैं। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब उनके मन में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र अभिलाषा जाग उठी। वे बदरिकाश्रम पहुँचे और अलकनंदा के पवित्र तट पर स्थित एक विशाल शिला पर बैठकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उन्होंने केवल वायु का सेवन किया और अपने मन, वचन तथा कर्म को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने तुरंत दिव्य स्वरूप में दर्शन नहीं दिए, बल्कि एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली। नारद ने उस वृद्ध में भी दिव्यता का अनुभव किया। तब भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए और नारद को साक्षात दर्शन देकर उन्हें अखंड भक्ति का वरदान प्रदान किया। उसी दिन से वह दिव्य शिला 'नारद शिला' के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज भी श्रद्धालु जब उस शिला के दर्शन करते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो वहाँ नारद मुनि का अखंड "नारायण-नारायण" का कीर्तन गूँज रहा हो।

भगवान विष्णु का वराह अवतार धर्म की रक्षा और पृथ्वी के उद्धार का प्रतीक माना जाता है। जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर सम्पूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया, तब भगवान ने वराह रूप धारण कर उसका वध किया और पृथ्वी माता को अपने दाँतों पर धारण कर पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। इस दिव्य कार्य के पश्चात भगवान बदरिकाश्रम आए और अलकनंदा के तट पर एक शिला पर बैठकर तप में लीन हो गए। उनका तप इतना दिव्य था कि वह शिला स्वयं भगवान की ऊर्जा से प्रकाशित हो उठी। कालांतर में वही शिला 'वाराही शिला' के नाम से विख्यात हुई। यह शिला भक्तों को यह संदेश देती है कि जब भी संसार पर अधर्म बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं।

भगवान के परम सेवक और वाहन गरुड़ की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। महर्षि कश्यप की पत्नी विनता के पुत्र गरुड़ जन्म से ही अद्भुत तेजस्वी, बलशाली और भगवान के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए देवताओं से अमृत प्राप्त किया और अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। किंतु उनके हृदय की सबसे बड़ी इच्छा भगवान श्रीहरि की सेवा करना थी। इसी अभिलाषा को लेकर वे बदरिकाश्रम पहुँचे और एक पैर पर खड़े होकर वर्षों तक कठिन तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और वर माँगने को कहा। गरुड़ ने विनम्र भाव से कहा कि वे सदैव भगवान के वाहन बनें, कभी पराजित न हों और जिस शिला पर उन्होंने तप किया है वह सदैव उनके नाम से प्रसिद्ध रहे। भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी सभी इच्छाएँ पूर्ण कर दीं। आज वही स्थान गरुड़ शिला के रूप में पूजित है। यह शिला भक्तों को यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का सर्वोच्च पुरस्कार भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करना है।

भगवान नृसिंह का अवतार भक्त प्रह्लाद की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था। जब हिरण्यकशिपु का अंत हुआ तब भगवान का उग्र स्वरूप देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। सभी ने प्रार्थना की कि प्रभु अपने क्रोध को शांत करें और पुनः करुणामय स्वरूप धारण करें। भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार कर बदरिकाश्रम आए और यहाँ तपस्या में लीन होकर अपने उग्र रूप को पूर्णतः शांत किया। जिस शिला पर उन्होंने निवास किया, वही आज नृसिंह शिला के रूप में प्रसिद्ध है। इस शिला के दर्शन करने से भक्तों के भीतर का भय समाप्त होता है और यह विश्वास जागृत होता है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं।

मार्कण्डेय ऋषि का जीवन भी भगवान की भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। वे भगवान नारायण के दर्शन की इच्छा लेकर बदरिकाश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक पवित्र शिला पर बैठकर "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का अनगिनत बार जप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और वरदान माँगने को कहा। ऋषि मार्कण्डेय ने न धन माँगा, न यश और न ही स्वर्ग। उन्होंने केवल इतना निवेदन किया कि उनके हृदय में भगवान की भक्ति कभी कम न हो और जिस शिला पर उन्होंने तप किया है, वहाँ भगवान का नित्य निवास बना रहे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वह स्थान 'मार्कण्डेय शिला' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह शिला आज भी प्रत्येक भक्त को यह प्रेरणा देती है कि सबसे बड़ा वरदान केवल भगवान की भक्ति है।

इन पाँचों दिव्य शिलाओं की महिमा केवल पुराणों की कथा नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का आधार है। बदरीनाथ धाम में आने वाला प्रत्येक भक्त इन शिलाओं के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानता है। अलकनंदा की कल-कल धारा, हिमालय की श्वेत चोटियाँ और भगवान बदरीविशाल की दिव्य उपस्थिति मिलकर ऐसा आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करती हैं कि मन स्वतः संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है।

कहा जाता है कि वैकुण्ठ में भगवान श्रीहरि जिस प्रकार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उसी प्रकार बदरीपुरी में वे इन पंचशिलाओं के माध्यम से आज भी अपने भक्तों के समीप विद्यमान हैं। इन शिलाओं को स्पर्श करने की अपेक्षा श्रद्धा से नमन करना ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि यहाँ पत्थर नहीं, बल्कि भगवान की दिव्य चेतना विराजती है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस - वडोदरा

वडोदरा जीएसएफसी में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस अंतर्गत सेमिनार आयोजित हुआ

▸▸ छोटाउदेपुर को औद्योगिक स्तर पर ले जाकर 'स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने का रोडमैप तैयार होगा

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए गुजरात ने 'विकसित गुजरात' का मजबूत रोडमैप तैयार किया : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावरहाउस बनाने में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा : केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया

वडोदरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गुजरात सरकार के विशिष्ट दृष्टिकोण 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट' अंतर्गत छोटाउदेपुर में सोमवार को स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हब और परंपरागत कौशल से औद्योगिक स्तर तक विषय पर वडोदरा जीएसएफसी में सेमिनार आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए गुजरात ने 'विकसित गुजरात' का मजबूत रोडमैप तैयार किया है। इसके अंतर्गत राज्य के संतुलित आर्थिक विकास के लिए पूरे गुजरात को कच्छ, सौराष्ट्र, कॉस्टल सौराष्ट्र, उत्तर, मध्य और सूरत – ऐसे छह प्रमुख इकोनॉमिक रीजन में विभाजित किया गया है। इन सभी क्षेत्रों के लिए फोकस सेक्टर निर्धारित किए गए हैं तथा उनकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 12 वर्षों के लगातार कार्यकाल से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल तक जो भी संकल्प सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए, उन्हें धरातल पर साकार करके दिखाया है। इसी कारण आज निवेशकों का सरकार पर अटूट विश्वास बना है। एक समय देश में असंभव मानी जाने वाली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात में चार बड़े प्लांटों के साथ तेजी से विकसित हो रही है। देश में पहली बार राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति-2026 घोषित कर उद्योगों को कैपिटल सब्सिडी और बिजली दरों में अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनने की देश में पहली बार अभूतपूर्व छूट प्रदान की है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2003 से प्रारंभ हुए 'वाइब्रेंट गुजरात' प्लेटफॉर्म की सफलता के कारण आज यह वैश्विक स्तर का मंच बन चुका है, जिससे राज्य में होने वाले एमओयू का क्रियान्वयन 70 से 90 प्रतिशत तक की उच्च दर से हो रहा है। उद्योगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर राज्य सरकार हमेशा सक्रिय रहकर समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने देश और राज्य के विकास के लिए सभी से मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया; ताकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित गुजरात का सपना साकार हो सके। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश की उभरती हुई स्पोर्ट्स इकोनॉमी में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एक मजबूत स्तंभ के समान है। भारत सरकार खेलों में आधारभूत स्तर से प्रतिभा की खोज, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास तथा वैश्विक स्तर के खेल उपकरणों के निर्माण तक समग्र इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाकर देश को वैश्विक स्पोर्टिंग पावरहाउस बनाने के लिए कटिबद्ध है। देश में 'खेलो इंडिया', 'फिट इंडिया मूवमेंट' तथा खेल के व्यापक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह में वृद्धि हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि खेलों में बढ़ती भागीदारी स्थानीय उत्पादन, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और निर्यात (एक्सपोर्ट) के लिए बड़े अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन अंतर्गत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स विकसित करने तथा भविष्य में होने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का लाभ उठाकर इस क्षेत्र के लिए समर्पित नीतिगत सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

इस अवसर पर छोटाउदेपुर की प्रभारी मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील ने भी राज्य के सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास में खेल क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर टेक्निकल सेशन में हेलो इंडिया के संयुक्त सचिव श्री विनिल कृष्णा तथा नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक श्री संजीत सिंह ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। छोटाउदेपुर की जिला कलेक्टर गार्गी जैन की अध्यक्षता में आयोजित पैनल डिस्कशन में केपीएमजी के पार्टनर प्रशांत शांतकुमारन, स्टैग इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री राकेश कोहली, शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा. लि. के एमडी एवं सीईओ श्री शिव प्रकाश सिंह, एगिलिटास के निदेशक श्री अजय कुमार पांडे, आनंदको स्पोर्टिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के आर एंड डी निदेशक श्री अर्जुन आनंद, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री मोनल चौकसी तथा खेल विभाग के निदेशक के. एम. हरिलाल (आईटीएस) ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। इस विचार-मंथन के दौरान उपयुक्त उत्पाद श्रेणियों की पहचान करने, आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता के मॉडल तैयार करने, एमएसएमई को प्रोत्साहित करने, बाज़ार तक पहुंच को मजबूत बनाने, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन पद्धतियां अपनाने तथा खेल उपकरण निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

वीजीआरसी मध्य गुजरात-वडोदरा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई स्थित आयरलैंड के कॉन्सुल जनरल श्री पैट्रिक डफी के साथ फलदायी बैठक आयोजित की

▸▸ आयरलैंड के उद्योगों-निवेशकों को गुजरात के विशाल निवेश एवं व्यापार अवसरों का लाभ उठाने का आमंत्रण

▸▸ आयरलैंड के कॉन्सुल जनरल श्री पैट्रिक डफी ने आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में सहभागी होने की उत्सुकता दर्शाई

▸▸ स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी तथा स्पोर्ट्स क्षेत्र में सहयोग को अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए परस्पर विचार-विमर्श

वडोदरा : वडोदरा में आयोजित हो रही मध्य गुजरात क्षेत्र की वीजीआरसी के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई स्थित आयरलैंड के कॉन्सुल जनरल श्री पैट्रिक डफी के साथ एक फलदायी बैठक आयोजित की।

इस बैठक में गुजरात-आयरलैंड के बीच आर्थिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने आगामी भारत-यूरोपीय संघ (इंडिया-ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से नए अवसरों के जो द्वार खुले हैं, उसके संदर्भ में आयरलैंड के उद्योगों तथा निवेशकों को गुजरात में उपलब्ध विशाल निवेश एवं व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रण दिया।

विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स क्षेत्र में सहयोग को अधिक प्रगाढ़ बनाने के विषय पर भी मुख्यमंत्री तथा कॉन्सुल जनरल ने चर्चाएँ कीं।

आयरलैंड के कॉन्सुल जनरल ने आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (वीजीजीआईएस)-2027 में सहभागी होने की उत्सुकता दर्शाई तथा परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के लिए कंट्री सेमिनार आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने वीजीजीआईएस-2027 में आने वाले आयरलैंड के प्रतिनिधिमंडल को पतंगोत्सव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एओयू) तथा अन्य उद्योगों की साइट विजिट कराने का सुझाव दिया।

इस बैठक में मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्री पी. भारती तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आपातकाल की वर्षगांठ पर लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर बहस आयोजित की गई

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। 1975 में आपातकाल की घोषणा की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, पिछले मंगलवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में "लोकतंत्र के लिए खतरे और आगे की चुनौतियां" विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन देश के चार प्रमुख मानवाधिकार संगठनों - पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) दिल्ली, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर), सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी (सीएफडी) और जन खट्टक द्वारा किया गया था।

इस कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञ, पत्रकार और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आपातकाल से मिले सबक पर विचार-विमर्श करने और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने मौजूद समकालीन चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक साथ आए। कारवां के संपादक थारुश बाल ने तर्क दिया कि आपातकाल को औपचारिक रूप से जन आंदोलनों और चुनावी हार के माध्यम से समाप्त किया गया था। आज भारतीय लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियाँ मौलिक रूप से भिन्न हैं। आपातकाल के दौरान, समाचार पत्रों पर खुलेआम सेंसरशिप लागू थी। आज, अधिकांश समकालीन मुख्यधारा के मीडिया औपचारिक सेंसरशिप के तहत काम करते हैं, क्योंकि उनका स्वामित्व सत्ताधारी प्रतिष्ठान की विचारधारा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

आज के दौर में मीडिया का स्वामित्व शक्तिशाली व्यावसायिक हितों के हाथों में केंद्रित है। संपादक थारुश बाले ने तर्क दिया कि धनी औद्योगिक समूहों का ऐतिहासिक रूप से मीडिया पर काफी प्रभाव रहा है और दावा किया कि उनके समाचार पत्रों की राजनीतिक और वैचारिक विचारधारा अक्सर हिंदुत्व के अनुरूप रही है। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक उदारीकरण ने समाचार संगठनों पर कॉरपोरेट प्रभाव को और मजबूत किया है। और विशेष रूप से स्वतंत्र डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनलों के उदय के साथ, लोग आज सच्चाई से अवगत हो रहे हैं। लेकिन इन चैनलों के पास निरंतर जमीनी रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं हैं। यह भी एक कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा।

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान इंडेक्स्ट बी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र प्रदान

दक्षिण गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट में केवल 11 ही दिनों में 350 कंपनियों को वाइब्रेंट में जोड़ने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री के करकमलों से प्रदान किया गया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान सोमवार को गुजरात सरकार के आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन संस्थान इंडेक्स्ट-बी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र प्रदान किया।

इंडेक्स्ट-बी ने 'के एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड' के साथ मिलकर गत 2 मई, 2026 को सूरत में आयोजित बिजनेस एक्सपोजिशन में केवल 11 दिनों में ही सर्वाधिक कुल 350 प्रदर्शकों को जोड़ने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए इंडेक्स्ट-बी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि इंडेक्स्ट-बी गुजरात सरकार के आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन संस्थान के रूप में निवेशकों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉण्टैक्ट के रूप में कार्य करता है। यह संस्थान निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मार्गदर्शन, आवश्यक सुविधाएँ तथा नीतिगत आधार प्रदान कर राज्य के औद्योगिक एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों ने इंडेक्स्ट-बी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अभिनंदन दिया और राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए उसके कार्य की सराहना की।

भावनगर मंडल के चार कर्मचारी डीआरएम संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित,सतर्कता कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित कार्रवाई से संभावित रेल दुर्घटनाएं टलीं

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में सुरक्षित रेल परिचालन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चार कर्मचारियों को उनकी असाधारण सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित निर्णय क्षमता के लिए वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री सी. आर. गरूडा की अनुशंसा पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा डीआरएम संरक्षा पुरस्कार (DRM Safety Award) से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर परा में आयोजित किया गया, जहां सभी सम्मानित कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र एवं मेडल प्रदान किए गए।

सम्मानित कर्मचारियों में श्री सुरेश डी. (कांटेवाला, जेतलसर), श्री सत्यजीत पांडेय (कांटेवाला, अलमपर), श्री जयेश वी. चौहान (प्वाइंट्समैन, वरतेज) तथा सुश्री हेमवर्षा एन. (पी. मैन, गोंडल) शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी सजगता एवं त्वरित कार्रवाई से संभावित रेल दुर्घटनाओं को टालते हुए सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक ने पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें भावनगर मंडल के सभी रेल कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा, सतर्कता और सेवा के प्रति समर्पण ही सुरक्षित रेल परिचालन की सबसे मजबूत आधारशिला है।

श्री सुरेश डी. ने 27 मार्च 2026 को समपार फाटक संख्या 62/सी पर ड्यूटी के दौरान ट्रेन संख्या 59557 पोरबंदर–भावनगर के इंजन के नीचे गियर बॉक्स की भारी लोहे की पिन लटकती हुई देखी। उन्होंने तत्काल खतरे का हाथ संकेत देकर स्टेशन मास्टर को सूचना दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारियों ने पिन को सुरक्षित रूप से बांधकर ट्रेन का संचालन सुरक्षित रूप से सुनिश्चित किया। उनकी सजगता से संभावित दुर्घटना टल गई।

श्री सत्यजीत पांडेय ने 11 मई 2026 को अलमपर स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान गुजर रही मालगाड़ी के 35वें वैगन में लटकता हुआ भाग देखा। उन्होंने तुरंत खतरे का संकेत देकर स्टेशन मास्टर को सूचित किया। समय रहते ट्रेन को रोककर दोष दूर किया गया और सुरक्षित रूप से आगे रवाना किया गया। उनकी सूझबूझ एवं तत्परता ने संभावित दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री जयेश वी. चौहान ने 3/4 मई 2025 को ट्रैफिक फाटक संख्या 214/सी पर ड्यूटी के दौरान वरतेज स्टेशन की लाइन संख्या-3 पर रेल फ्रैक्चर (Rail Fracture) देखा। उन्होंने बिना विलंब स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने तत्काल मरम्मत कर संभावित गंभीर रेल दुर्घटना को टाल दिया। सुश्री हेमवर्षा एन. ने 13 जून 2026 को गोंडल स्थित समपार फाटक संख्या 48-बी पर ड्यूटी के दौरान एक मालगाड़ी के दो वैगनों में असामान्य स्पार्किंग देखी। उन्होंने तुरंत वीरपुर के डिप्टी स्टेशन मास्टर को सूचना दी। जांच में एक वैगन में ब्रेक बाइंडिंग तथा दूसरे में मेटल डिपॉजिट पाया गया। समय रहते दोष दूर कर ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया। उनकी सतर्कता एवं कर्तव्यनिष्ठा ने संभावित दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी सम्मानित कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि सुरक्षा के प्रति सजग और समर्पित कर्मचारी ही भारतीय रेल की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों से भविष्य में भी इसी प्रकार सतर्कता, अनुशासन एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति के साथ सुरक्षित रेल संचालन में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल अपने कर्मचारियों की सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली की सराहना करता है। ऐसे समर्पित कर्मचारियों के प्रयास न केवल सुरक्षित रेल परिचालन को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि यात्रियों, रेल संपत्ति एवं राष्ट्रीय संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा के साथ मंडल के सभी शाखाधिकारी उपस्थित थे।

'सुजलाम सुफलाम जल अभियान' के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता में इस वर्ष 20,789 लाख घन फीट की वृद्धि : जल संसाधन राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल

▸▸ 'जल अभियान' के माध्यम से पिछले आठ वर्षों में जल संग्रहण क्षमता में कुल 1,38,039 लाख घन फीट की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि

▸▸ चालू वर्ष में 13,315 कार्य पूर्ण, 2.30 लाख मानव दिवस का मिला रोजगार

▸▸ पिछले 8 वर्षों में जल संचयन के 1.23 लाख से अधिक कार्य संपन्न

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'कैच द रेन' अभियान अंतर्गत समग्र राज्य में पानी के संग्रहण का दायरा बढ़ाने तथा भूमिगत स्तर को ऊँचा लाने के उम्दा आशय के साथ चलाया जा रहा 'सुजलाम सुफलाम जल अभियान' जन भागीदारी के माध्यम से एक शानदार जन आंदोलन बन चुका है।

जल संसाधन एवं जलापूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल ने बताया कि इस वर्ष 'सुजलाम सुफलाम जल अभियान' के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता में 20,789 लाख घन फीट की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले 8 वर्षों में राज्य की जल संग्रहण क्षमता में रिकॉर्ड तोड़ कुल लगभग 1,38,039 लाख घन फीट की वृद्धि दर्ज हुई है। पानी बचाने और उसका व्यय रोकने के लिए जन मानस में जागरूकता आए; ऐसी दीर्घदृष्टि के साथ पिछले 08 वर्षों से यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से गत 23 फरवरी, 2026 को गांधीनगर से इस अभियान का राज्यव्यापी भव्य शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में चालू वर्ष में समग्र राज्य में मई-2026 तक विभिन्न विभागों के समन्वय से कुल 13,315 कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं।

इस अभियान अंतर्गत परंपरागत जल स्रोतों के नवीनीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसमें चालू वर्ष में मुख्यतः तालाबों को गहरा करने के 2,450 कार्य, चेकडैम डिसिल्टिंग के 3,661 कार्य तथा चेकडैम रिपेयरिंग के 1,160 कार्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त; 626 किलोमीटर लंबाई में नहरों तथा 1,277 किलोमीटर लंबाई में नालों की साफ-सफाई की गई है। इन कार्यों के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता में 20,789 लाख घन फीट की वृद्धि हुई है। इसके साथ श्रमिकों के लिए लगभग 2.30 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है।

जल संसाधन राज्य मंत्री ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के 6 प्रमुख विभाग जल संसाधन, जलापूर्ति विभाग, वन एवं पर्यावरण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास विभाग और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इन कार्यों की मुख्यतः तीन पद्धतियाँ हैं; जिनमें जन भागीदारी, मनरेगा योजना और विभागीय रूप से कार्य पूर्ण किए जाते हैं।

उन्होंने इस अभियान की उपलब्धियाँ बताते हुए कहा कि दीर्घकालिक योजना तथा कड़े परिश्रम के परिणामस्वरूप पिछले 8 वर्षों में कुल 1,23,635 कार्य शुरू किए थे। इनमें से मुख्य रूप से तालाबों को गहरा करने एवं नए तालाबों के 39,770 कार्य, चेकडैम डिसिल्टिंग के 26,873 कार्य तथा चेकडैम रिपेयरिंग के 7,810 कार्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने जोड़ा कि इसके अतिरिक्त; कुल 80,793 किलोमीटर लंबाई में नहरों तथा नालों की साफ-सफाई के कार्य शुरू किए गए थे, जिसके कारण जल संग्रहण क्षमता में कुल 1,38,039 लाख घन फीट की वृद्धि हुई है, जिसमें 206.73 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद - मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाई गई

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद एवं मंगलुरु के बीच स्पेशल किराए पर संचालित की जा रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की अवधि का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। अब यह ट्रेन 31 जुलाई 2026 तक अतिरिक्त फेरों के साथ संचालित की जाएगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा उपलब्ध होगी तथा अतिरिक्त यात्री यातायात का सुचारु प्रबंधन किया जा सकेगा।

ट्रेन संख्या 09424 अहमदाबाद – मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक शुक्रवार) [05 फेरे]

ट्रेन संख्या 09424 प्रत्येक शुक्रवार को 03 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक अहमदाबाद से 16:00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 21:00 बजे मंगलुरु जंक्शन पहुंचेगी।

प्रमुख ठहराव:

यह ट्रेन नडियाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, सावर्डा, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली, मडगांव, काणकोण, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मूकाम्बिका रोड बैंदूर, कुंदापुरा, उडुपी, मुल्की एवं सुरतकल स्टेशनों पर ठहरेगी।

कोच संरचना:

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध रहेंगे।

बुकिंग जानकारी:

ट्रेन संख्या 09424 की बुकिंग 30 जून, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय, ठहराव एवं अन्य विवरण की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

मणिपुर में आर्थिक नाकाबंदी के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। मणिपुर, जो पिछले तीन वर्षों से देश में अशांति का कारण बना हुआ है, आज दो समुदायों के बीच शत्रुता के चलते और भी भड़क उठा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसके चलते आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। मणिपुर के कुकी समुदाय बहुल कांग पोकपी जिले में लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। 50 किलो चावल की बोरी की कीमत 1,400 रुपये से बढ़कर 1,700 रुपये और फिर 4,000 रुपये हो गई है। वहीं, कालाबाजारी में खाना पकाने के गैस सिलेंडर की कीमत 5,000 रुपये तक पहुंच गई है। पेट्रोल भी अब 250 रुपये से 280 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। हाल ही में नागा समूहों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर विरोध प्रदर्शन और यातायात अवरोधन के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने छह अपहृत नागाओं की हत्या के लिए न्याय की मांग की थी। इन प्रतिबंधों के कारण पहाड़ी जिलों में ईंधन टैंकरों और खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्री ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही काफी कम हो गई है। इनमें से कुछ ट्रकों को जला दिया गया है। आपूर्ति की कमी के कारण कई लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग करने को मजबूर हैं। मणिपुर की आज यही स्थिति है!!!

पश्चिम रेलवे
अहमदाबाद मण्डल
शुद्धिपत्र
ई-निविदा सूचना सं. 1, 2026-27 में शुद्धिपत्र
निविदा सं. CWMCPOHADI2026-27-3
कार्य का नाम : CPOH अहमदाबाद अंतर्गत 120 ट्रैक मशीनो की 03 वर्ष के लिए POH संबंद्ध मरम्मत । **संशोधित विज्ञापन NIT लागत :** ₹ 1,35,86,57,615.03/- **संशोधित ईएमडी लागत रु. में:** ₹ 2,71,73,200.00/- **संशोधित निविदा बंद होने एवं निविदा खुलने की तारीख:** दिनांक 31/07/2026 को 15:00 बजे एवं दिनांक 31/07/2026 को 15:15 बजे, **IREPS पर निविदा अपलोड करने की तारीख:** 09/06/2026, **शुद्धिपत्र जारी करने की तारीख: 27/06/2026** ADI-083
हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं निवेशकों का वीजीआरसी के डिस्कशन्स को डिसीजन में, आइडियाज को प्रोजेक्ट्स में और प्रोजेक्ट्स को प्रॉस्पेरिटी में परिवर्तित करने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विशिष्ट सोच तथा समय से आगे का विचार कर उसके इम्प्लिमेंटेशन की प्रतिबद्धता से भारत प्रत्येक क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ा है
- श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप के कारण दुनिया के देश भारत के साथ विश्वसनीय मित्र के भाव से जुड़े हैं और अधिक से अधिक देश जुड़ रहे हैं
- प्रधानमंत्री ने बैलेंस्ड ग्रोथ का जो विचार दिया, उसे गुजरात ने वीजीआरसी से आगे बढ़ाया है, आज गुजरात 'ग्लोबल गेटवे टू द फ्यूचर' बना है
- वीजीआरसी केवल निवेश का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि स्थानीय उद्योगों को वैश्विक अवसरों के साथ जोड़ने का सशक्त माध्यम है
- मध्य गुजरात को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग तथा इनोवेशन हब बनाने की दिशा में वीजीआरसी एक महत्वपूर्ण कदम बनेगी
- ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, फार्मा, एग्री-फूड प्रोडक्ट्स तथा एमएसएमई क्षेत्र में मध्य गुजरात का महत्वपूर्ण योगदान

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की चौथी कड़ी का शुभारंभ कराया

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की प्रेरक उपस्थिति

वाइब्रेंट गुजरात अब केवल इन्वेस्टमेंट समिट नहीं, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप और इनोवेशन की प्रतीक : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-मध्य गुजरात के मंच से राज्य के विकास, औद्योगिक शक्ति और भविष्य के अवसरों को उजागर किया गया

वडोदरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मध्य गुजरात क्षेत्र की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का सोमवार को वडोदरा से शुभारंभ कराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विशिष्ट सोच तथा समय से आगे का विचार कर उसका इम्प्लिमेंटेशन करने की प्रतिबद्धता के कारण भारत प्रत्येक क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप के कारण दुनिया के देश भारत के साथ विश्वसनीय मित्र के भाव से जुड़े हैं तथा अधिक से अधिक देश भी जुड़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्ष के सफल सुशासन में भारत ने अर्थव्यवस्था, उद्योग तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। इतना ही नहीं; प्रधानमंत्री ने उद्योगों को रेड टैपिज्म से बाहर लाकर रेड कारपेट से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे आगे बढ़ाते हुए राज्य के जिलों के औद्योगिक एवं स्थानीय विकास को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'लोकल टू ग्लोबल' की मंशा रीजनल वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंसों से पूरी हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उद्योग जगत के अग्रणियों, निवेशकों तथा उद्यमियों से वीजीआरसी में होने वाले डिस्कशन को डिसीजन में, आइडियाज को प्रोजेक्ट्स में और प्रोजेक्ट्स को प्रॉस्पेरिटी में परिवर्तित करने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

उन्होंने इस वीजीआरसी को केवल निवेश का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि स्थानीय उद्योगों को वैश्विक अवसरों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बताते हुए जोड़ा कि मध्य गुजरात के 10 जिलों को समाहित करने वाली दो दिवसीय वीजीआरसी में राज्य के इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के नए अवसरों एवं भागीदारी को मंच देने का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने वीजीआरसी को संतुलित विकास का नया मॉडल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए बैलेंस्ड ग्रोथ के विचार को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। मेहसाणा, राजकोट और सूरत में आयोजित तीन वीजीआरसी की सफलता के बाद अब मध्य गुजरात में दो दिवसीय चौथी वीजीआरसी आयोजित हो रही है। उन्होंने गौरव के साथ कहा कि अब तक आयोजित हुईं तीनों वीजीआरसी में कुल 9,499 एमओयू द्वारा लगभग 13.30 लाख करोड़ रुपए का निवेश राज्य में आया है।

मुख्यमंत्री ने मध्य गुजरात को राज्य के विकास का हृदय बताते हुए कहा कि वडोदरा, आणंद, खेडा, पंचमहाल, छोटाउदेपुर तथा दाहोद जैसे जिले मैन्युफेक्चरिंग, इंजीनियरिंग, फार्मा, एग्री-फूड प्रोडक्ट्स और एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने भूमिका देते हुए कहा कि वडोदरा पेट्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, ईवी इक्विपमेंट तथा टाटा एयरबस सी-295 जैसे एयरोस्पेस प्रोजेक्ट्स के कारण नए औद्योगिक क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहा है। आणंद देश का मिल्क कैपिटल है तथा अमूल ब्रांड विश्वभर में भारत की पहचान बना है और खेडा जिले में फूड प्रोसेसिंग व एमएसएमई क्षेत्र में बड़ी संभावनाएँ विद्यमान हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस बात का भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से वर्ष 2003 में शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात बिजनेस समिट की दो दशकों की सफलता से गुजरात आज ग्लोबल गेटवे टू द फ्यूचर बना है।

उन्होंने कहा कि जब इस प्रकार की बिजनेस समिट आयोजित करने का विचार भी कोई नहीं कर सकता था, तब श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वभर के निवेशकों को गुजरात लाने का सपना देखा था, जो आज साकार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात आज बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बना है और ग्लोबल सप्लाई चेन में उद्योगों की भागीदारी मजबूत बनाने एवं उसे और गति देने के लिए राज्य सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026 घोषित की है। इस पॉलिसी में एमएसएमई, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स तथा नए उद्योग क्षेत्रों के लिए अनेक इंडस्ट्री फ्रेंडली इंसेंटिव्स को शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि पहली बार 'चूज योर इंसेंटिव्स' जैसी नई पहल इस पॉलिसी में की गई है, जिसमें उद्योग अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसेंटिव्स का चयन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात को पॉलिसी ड्रिवन स्टेट की पहचान दिलाई है। आज गुजरात मजबूत नीतिगत ढाँचे, गुड गवर्नेंस, आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा तेज निर्णय प्रक्रिया के कारण अग्रसर बना है और हमने पॉलिसी ड्रिवन स्टेट से विकसित भारत बनने की दिशा अपनाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत और ग्रीन ग्रोथ जैसे अभियानों के साथ गुजरात नई अर्थव्यवस्था के निर्माण में अग्रिम योगदान दे रहा है। उन्होंने विकसित गुजरात से विकसित भारत @2047 का संकल्प साकार करने के लिए उद्योग, व्यापार तथा इनोवेशन की शक्ति के साथ आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोई भी निवेशक निवेश करने से पहले विचार करता है कि जहाँ वह निवेश कर रहा है, वह स्थान निवेश के लिए कितना उचित है। क्या यह वह स्थान है, जहाँ उसका उद्योग विश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इस उद्देश्य को और सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। निवेशकों को यह विश्वास होना चाहिए कि उन्हें सरकार की स्थिर नीतियाँ, विश्वसनीय बिजली, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा तथा उद्योग संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था मिलेंगी, जिससे उनका उद्योग सफल हो। यह विश्वास ही गुजरात की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से गुजरात में पॉलिसी स्टेबिलिटी, कुशल प्रशासन और विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो इसे वैश्विक निवेश का प्रमुख केन्द्र बनाता है। वाइब्रेंट गुजरात उसी विचार का प्रतीक है, जहाँ सरकार तथा उद्योग विकास के भागीदार हैं। यह विचार ही आज भारत की विकास यात्रा का आधार बना है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए रिलायेबल पावर बहुत आवश्यक है। रिलायेबल पावर ही मजबूत अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। गुजरात इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है। उद्योगों, एमएसएमई, डेटा सेंटर, मेट्रो रेल और नई तकनीकों के लिए बिजली व्यवस्था का उचित आयोजन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत की सबसे पीक पावर डिमांड इस वर्ष 271 गीगावाट रही है, जिसकी हमने पूर्ति की है। हमारी 284 गीगावाट तक की तैयारी थी। आगामी वर्षों में डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहनों और एआई के कारण पावर डिमांड बढ़ेगी। इसलिए हमने 300 गीगावाट तक की तैयारी कर रखी है। यह केवल तकनीकी आयोजन नहीं, बल्कि वर्षों की योजना और उसमें सुधार तथा पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजनाएँ बनीं, उसका परिणाम है।

उन्होंने कहा कि आज भारत वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं के समय भी हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाए रखा है तथा आर्थिक स्थिरता भी रही है। भारत को लेकर आशंकाएँ व्यक्त की जा रही थीं, लेकिन हमने भारत में स्थिरता बनाकर रखी है।

उन्होंने कहा कि गुजरात प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। यह पावर सरप्लस राज्य है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी गुजरात देश का नेतृत्व कर रहा है। राज्य में 50 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्थापित की गई है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में गुजरात ने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण भी स्थापित किया है। गुजरात ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि शहरी विकास क्षेत्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पीएमएवाई (शहरी) एक बहुत बड़ी योजना घोषित की गई है। वर्तमान में पीएमएवाई एवं पीएमएवाई 2.0 अंतर्गत 1 करोड़ 27 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 98.6 लाख आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। गुजरात में भी इन योजनाओं के अंतर्गत 11.5 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

ऐतिहासिक नगरी वडोदरा में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-मध्य गुजरात के मंच से गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा, "अब वाइब्रेंट गुजरात केवल एक इन्वेस्टमेंट समिट नहीं, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का प्रतीक बन गई है। यह इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात लगातार आर्थिक बदलाव का साक्षी बन रहा है।"

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य गुजरात एक ऐसी भूमि है, जहां इतिहास, नवाचार और संस्कृति एक साथ साँस लेते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य गुजरात ने हर युग में देश को एक नई दिशा दिखाई है। वडोदरा की कला, कौशल, शिक्षा और नवाचार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। विरासत से लेकर पर्यटन तक, इस क्षेत्र ने गुजरात का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन किया है। दुनिया को सहकारिता का मार्ग दिखाने वाला सहकारी आंदोलन भी इस भूमि से शुरू हुआ था।

उन्होंने पंचमहाल, महिसागर, दाहोद और छोटा उदेपुर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि नर्मदा जिले में स्थित दुनिया की सबसे ऊँची 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' आज पूरे भारत के गौरव का प्रतीक बन गई है।

मध्य गुजरात की औद्योगिक क्षमता पर प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, "हम न केवल इतिहास की गाथा कह रहे हैं, बल्कि भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। गुजरात के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में मध्य गुजरात क्षेत्र का योगदान लगभग 28 फीसदी है। वर्ष 2025-26 में यहां से 20.5 अरब डॉलर से अधिक के उत्पाद निर्यात किए गए हैं, जो दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "आज मध्य गुजरात में 65 से अधिक जीआईडीसी एस्टेट हैं, जिनमें 24,000 से अधिक औद्योगिक प्लॉट सक्रिय हैं। गुजरात के 92 फीसदी ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, 70 फीसदी बेवरेज प्रोसेसिंग, 63 फीसदी फार्मास्युटिकल्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मध्य गुजरात का महत्वपूर्ण योगदान है। हम न केवल ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि हम उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं।"

उप मुख्यमंत्री ने कहा, "यह मध्य गुजरात की प्रगति की केवल शुरुआत भर है। सेंट्रल गुजरात इकोनॉमिक मास्टर प्लान के अंतर्गत आगामी 20 वर्षों की विकास ब्लूप्रिंट तैयार की गई है।"

उन्होंने कहा कि इस आयोजन के तहत छोटाउदेपुर को भारत का अगला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हब बनाया जाएगा और वडोदरा को देश का सबसे बड़ा बायोइकोनॉमी हब बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "विकसित गुजरात औद्योगिक पॉलिसी 2026 के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।"

उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी का अहम पहलू महिला सशक्तिकरण है। महिला उद्यमियों को 360-डिग्री सपोर्ट फ्रेमवर्क दिया जाएगा। उन्हें अतिरिक्त 1 फीसदी ब्याज सब्सिडी, करियर ब्रेक के बाद वापस आने वालीं महिलाओं के लिए स्किल रिफ्रेशर कोर्स और पांच वर्षों तक 75 फीसदी रेंटल असिस्टेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के जरिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने और 3000 रोजगार के अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य है। दिव्यांग भाई-बहनों को रोजगार देने वाली कंपनियों को भी राज्य सरकार की ओर से 5 से 10 वर्षों तक ईपीएफ रीइंबर्समेंट का संपूर्ण सहयोग दिया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा, "गुजरात ने उद्योगों के लिए तेज और पारदर्शी सुशासन का मॉडल स्थापित किया है। गत दो वर्षों में इंसेंटिव डिस्बर्समेंट में 55 फीसदी की वृद्धि हुई है और वह 7888 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।"

उन्होंने आगे कहा कि आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों में 41 फीसदी की कमी की गई है, लंबित फाइलों में 95 फीसदी की कमी दर्ज की गई है और आज रोजाना लगभग 392 आवेदन क्लियर हो रहे हैं। यह तेज कार्यान्वयन, पारदर्शिता और नीतिगत स्थिरता गुजरात को निवेश के लिए विश्वसनीय स्थान बनाते हैं।

निवेशकों को आमंत्रण देते हुए श्री हर्ष संघवी ने कहा, "वाइब्रेंट गुजरात का यह मंच केवल एमओयू पर हस्ताक्षर करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह सपनों का साकार करने का अवसर है। मैं हर निवेशक, स्टार्टअप फाउंडर और उद्योग जगत के अग्रणियों को आमंत्रित करता हूं कि आइए, हम विकस की इस नई गाथा का हिस्सा बनें, अवसरों को निवेश में और साहस को समृद्धि में बदलें।"

उन्होंने आगे कहा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत@2047' के संकल्प को साकार करने के लिए विकसित गुजरात का इंजन तीव्र गति से दौड़ रहा है। आइए, हम सभी मिलकर एक नया मध्य गुजरात बनाएं।"

वीजीआरसी के उद्घाटन सत्र में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, वरिष्ठ सचिव और उद्योग-व्यापर जगत के अग्रणी सहित विभिन्न देशों के राजदूत और बड़ी संख्या में युवा उद्यमी मौजूद रहे।

पश्चिम रेलवे वसई रोड के रास्ते वलसाड वेलांकन्नि – डहाणू रोड के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से वलसाड – वेलांकन्नि – डहाणू रोड स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09030/09029 वलसाड – वेलांकन्नि – डहाणू रोड स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09030 वलसाड–वेलांकन्नि स्पेशल वलसाड से शुक्रवार, 03 जुलाई, 2026 को 18.25 बजे प्रस्थान करेगी तथा रविवार को 10.00 बजे वेलांकन्नि पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09029 वेलांकन्नि – डहाणू रोड स्पेशल वेलांकन्नि से सोमवार, 06 जुलाई, 2026 को 00.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 10.30 बजे डहाणू रोड पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में पालघर, वसई रोड, पनवेल, लोनावला, पुणे, दौंड, सोलापुर, कलबुरगि, वाडी, यादगिर, कृष्णा, रायचूर, मंत्रालयम रोड, आदोनि, गुंतकल, गुत्ती, ताडिपत्रि, यर्रगुंटला, कड़पा, राजमपेटा, रेणिगुंटा, काटपाडी, वेलूर छावनी, तिरुवण्णामलै, विल्लुपुरम, तिरुप्पादिरिप्पुलियूर, चिदम्बरम, मइलाडुतुरै, तिरुवल्लूर, कारैक्काल, नागूर और नागप्पट्टिनम स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09030 का डहाणू रोड स्टेशन पर एक अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09030 की बुकिंग 30.06.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात को निवेश, विकास और रोजगार क्षेत्र में अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए 8 नए औद्योगिक एस्टेट बनाने की घोषणा की

गुजरात में उद्योगों के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खेड़ा, अहमदाबाद, पंचमहाल, छोटाउदेपुर और भावनगर जिले में 3611 एकड़ क्षेत्र में कार्यरत होंगे स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट

खेड़ा के महीज, सरखेज, अंघाड़ी और महिसा, अङमदाबाद के मांडल, पंचमहाल के नदीसर, छोटाउदेपुर के ऊंडवा तथा भावनगर के मोणपुर में बनेंगे नए औद्योगिक एस्टेट

वडोदरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने निवेश, विकास और रोजगार क्षेत्र में गुजरात को और भी विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) की वडोदरा में आयोजित चौथी कड़ी में विभिन्न जिलों में 8 नए औद्योगिक एस्टेट (जीआईडीसी) स्थापित करने की घोषणा की। राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए इन स्मार्ट एस्टेट्स के द्वारा आधुनिक सुविधाएं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। ये स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट खेड़ा, अहमदाबाद, पंचमहाल, छोटाउदेपुर और भावनगर जिले में 3611 एकड़ क्षेत्र में आकार लेंगे। तदनुसार, खेड़ा जिले के महीज जीआईडीसी को 130.3 एकड़ क्षेत्र में, कठलाल तहसील के सरखेज जीआईडीसी को 332.7 एकड़ क्षेत्र, महुधा तहसील के महिसा जीआईडीसी को 18.5 एकड़, गळतेश्वर तहसील के अंघाड़ी जीआईडीसी को 310.9 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, अहमदाबाद जिले के मांडल जीआईडीसी को 515.2 एकड़ क्षेत्र में, पंचमहाल जिले की गोधरा तहसील के नदीसर जीआईडीसी को 105.5 एकड़ क्षेत्र में, छोटाउदेपुर जिले की जेतपुर पावी तहसील के उंडवा जीआईडीसी को 247.1 एकड़ क्षेत्र में और भावनगर जिले की वल्भीपुर तहसील के मोणपुर जीआईडीसी को 1950.7 एकड़ क्षेत्र में नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई।

इस घोषणा के अंतर्गत गुजरात के विभिन्न जिलों में कुल 3611 एकड़ क्षेत्र में नए इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित किए जाएंगे। इस आयोजन से मध्य गुजरात में औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा स्थानीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के लिए प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के साथ सुव्यवस्थित औद्योगिक एस्टेट्स का निर्माण, निवेशकों के लिए सरलता और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

वीजीआरसी मध्य गुजरात-वडोदरा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की रूसी महासंघ के व्यापार प्रतिनिधित्व में सरकारी संबंधों एवं वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख श्री ज्लाटा अंतुशेवा के साथ फलदायी बैठक हुई

वडोदरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा में चल रही मध्य गुजरात क्षेत्र की द्विदिवसीय वीजीआरसी के प्रथम दिन सोमवार को वन-टू-वन बैठकों की श्रृंखला के अंतर्गत भारत में रूस के व्यापार प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक आयोजित की।

इस बैठक में उन्होंने परिवहन, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, पेमेंट सिस्टम के अलावा भारतीय एमएसएमईस, आईएनआर-आधारित वित्तीय लेन-देन जैसे क्षेत्रों में तथा रूस की आर्केम (स्पेशियलिटी केमिकल्स) और यूरोकेम (उर्वरक) कंपनियों के साथ पारस्परिक सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में परस्पर चर्चा-विमर्श किया।

इस बैठक में मुख्य सचिव श्री मनोज दास, उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री अश्विनी कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार तथा मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे उपस्थित रहे।

'क्लीन सिटी-ग्रीन सिटी' के संकल्प की ओर वडोदरा का मजबूत कदम

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेरक उपस्थिति में वडोदरा में 'पीएम ई-बस सेवा' योजना के तहत 30 एसी इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया

वडोदरा शहर की जनता को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन सेवा की सौगात, कुल 250 इलेक्ट्रिक बसों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का दृढ़ संकल्प

वडोदरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेरक उपस्थिति में सोमवार को वडोदरा में आयोजित 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' के दौरान जीएसएफसी गेट नंबर-1 से 30 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

वडोदरा महानगर पालिका ने शहर को 'क्लीन सिटी-ग्रीन सिटी' बनाने के संकल्प के साथ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएम ई-बस सेवा' योजना के तहत इस पर्यावरण-अनुकूल परिवहन क्रांति की शुरुआत की है।

वडोदरा शहर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पहले मंजूर की गई 100 बसों के स्थान पर अब कुल 250 एसी इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। इस योजना के पहले चरण में कुल 130 बसें आवंटित की जाएंगी, जिसके अंतर्गत इस सुविधा का प्रारंभ किया गया है।

ये इलेक्ट्रिक बसें 'जीरो एमिशन' टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होने के कारण शहर में कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी और नागरिकों को शुद्ध हवा में यात्रा करने का लाभ मिलेगा। ये सभी बसें संपूर्ण वातानुकूलित (एसी) और आवाज-रहित होने से यात्रा अधिक सुखद और आरामदायक होगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैसेंजर काउंटिंग सिस्टम और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, दुर्घटना के समय सुरक्षा के लिए फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र) और फर्स्ट एड किट की सुविधा भी उपलब्ध है। ये बसें व्हीलचेयर एक्सेसिबल हैं। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता वाली सीटंध तथा महिलाओं के लिए विशेष 'पिंक सीटें' आरक्षित की गई हैं। चुनिंदा ब सों में हाइड्रोलिक लिफ्ट और रैम्प की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, आधुनिक यात्रा अनुभव के लिए डिजिटल टिकटिंग, लाइव ट्रैकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम और अनाउंसमेंट के लिए 'पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम' कार्यरत रहेंगे। नागरिक नकद के अलावा यूपीआई, टिकटिंग कार्ड और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए टिकट खरीद सकते हैं।

बसों के सुचारु संचालन के लिए गोत्री, सयाजीगंज, निजामपुरा, सयाजीपुरा और मकरपुरा में विशेष चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील, विधानसभा में मुख्य सचेतक श्री बालकृष्ण शुक्ल, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, कई विधायक और पदाधिकारियों सहित अग्रणी उपस्थित रहे।

वडोदरा महानगर पालिका की यह पर्यावरण-अनुकूल पहल केवल यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण देने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। इन इलेक्ट्रिक बसों के आगमन से वडोदरा के सार्वजनिक परिवहन ढांचे में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

दिल्ली की नई ईवी नीति से परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स माफी से लेकर लाखों की सब्सिडी तक

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स में भारी छूट, प्रत्यक्ष सब्सिडी, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन और चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की व्यापक योजना तैयार की गई है। सरकार का मानना है कि इस नीति के लागू होने से न केवल राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम होगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई ईवी नीति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक दिल्ली को स्वच्छ, आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त परिवहन व्यवस्था की दिशा में अग्रसर करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है और परिवहन क्षेत्र से निकलने वाला धुआं इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी आधारित वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम किया जा सके। नई नीति के तहत सबसे बड़ी राहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले उपभोक्ताओं को दी गई है। सरकार ने घोषणा की है कि 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इससे नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी और उनकी शुरुआती लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। सरकार का मानना है कि टैक्स छूट मिलने से मध्यम वर्ग के उपभोक्ता भी इलेक्ट्रिक कारों की ओर तेजी से आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रोत्साहन योजना तैयार की है। नई नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदने वालों को पहले तीन वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहले वर्ष वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। दूसरे वर्ष यह राशि 20 हजार रुपये होगी, जबकि तीसरे वर्ष 10 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह योजना युवाओं, छात्रों और रोजमर्रा के उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को भी नई नीति में विशेष महत्व दिया गया है। ऑटो चालकों और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहले वर्ष 50 हजार रुपये, दूसरे वर्ष 40 हजार रुपये और तीसरे वर्ष 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद पर भी एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन प्रस्तावित किया गया है, जिससे माल परिवहन क्षेत्र में भी स्वच्छ ऊर्जा आधारित वाहनों का उपयोग बढ़ सके। सरकार ने राजधानी में पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की स्पष्ट समयसीमा भी तय कर दी है। नई नीति के अनुसार 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा का ही नया पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद नए पेट्रोल और सीएनजी ऑटो का पंजीकरण बंद हो जाएगा। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन के इस महत्वपूर्ण हिस्से को इलेक्ट्रिक बनाने से प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी और परिचालन लागत भी घटेगी। इसी क्रम में दोपहिया वाहनों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही नया पंजीकरण किया जाएगा। यानी इसके बाद पेट्रोल आधारित नई मोटरसाइकिलों और स्कूटरों का पंजीकरण नहीं होगा। इस कदम को राजधानी के परिवहन क्षेत्र में सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इसके लिए चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं और आवश्यक आधारभूत ढांचे का विस्तार भी समानांतर रूप से किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। नई ईवी नीति में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। यदि कोई वाहन मालिक बीएस-4 या उससे नीचे के मानक वाले अपने पुराने वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर जमा कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे एक लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि पुराने प्रदूषणकारी वाहन सड़कों से हटें और उनकी जगह स्वच्छ तकनीक वाले इलेक्ट्रिक वाहन लें। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाइब्रिड वाहनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह नीति पूरी तरह बैटरी आधारित इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार ने ईवी से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने की घोषणा की है। इस पोर्टल के माध्यम से वाहन खरीदने वाले नागरिक सब्सिडी, टैक्स छूट, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन तथा अन्य सभी सरकारी लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।